'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि- 15 नवंबर, 2014

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 17 ● अंक 24 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 नवंबर, 2014

डॉ. उदित राज ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम जौन्ती को लिया गोद

रेखा वोहरा

नई दिल्ली, 11 नवंबर, 2014 । डॉ. उदित राज ने वार्ड संख्या-29, मुंडका विधान सभा क्षेत्र-8 के जौन्ती गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत एक आदर्श गांव के विकास के लिए चुना है।

गांव जौन्ती का परिचय :

उत्तर पश्चिम दिल्ली के बाहरी जिला में जौन्ती गांव स्थित है। यह कंझावला कुतुब गढ़ रोड पर स्थित है और इसका अधिकतर भाग गांव कटेसर द्वारा उत्तरी दिशा से घिरा हुआ है और इसके दक्षिणी दिशा में गढ़ी, रिंडाला पूर्व में लाडपुर और पश्चिम में हरियाणा के खैरपुर मुकुंदपुर और कैनंदा आदि गांव स्थित है। भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार, गांव का कुल क्षेत्रफल 9,199 बीघा 12 बीसवा है। इस क्षेत्र में लगभग 5800 बीघा भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है, 383 बीघा 3 बीसवा भूमि पर ग्राम सभा है और शेष भूमि पर आबादी, सड़कें, नहर, विद्यालय, खेल का मैदान, जोहड़, पार्क आदि है। इस प्रकार गांव का बड़ा भूभाग कृषि कार्यकलाप के लिए प्रयोग होता है। गांव की कुल आबादी 6,000 है। गांव में विभिन्न जाति व समुदाय के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं और गांव किसी भी प्रकार के जातीय व साम्प्रदायिक विवाद से आज तक अछूता है।

मूलभूत सुविधाएं एवं किए जाने वाले विकास के मुख्य बिन्दु :

1. *अस्पताल :* दिल्ली स्वास्थ्य योजना विभाग 1977 से 50 बिस्तर के अस्पताल बनाने के लिए ग्राम सभा की जमीन पर प्रयास किया जा रहा है, किन्तु 18 वर्षों से किसी निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। इस विषय के लिए तात्कालिक कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्तमान में दिल्ली स्वास्थ्य स्कीम द्वारा डिस्पेंसरी चलायी जा रही है। इसमें डॉक्टरों एवं दवाइयों की काफी कमी है।

2. *खेल :* गांव में 8 बीघे में बना हुआ शारीरिक शिक्षा केन्द्र है। इसे उत्तरी नगर निगम के नरेला जोन द्वारा विकसित किया जाना है, ताकि नौजवान बच्चे व ग्रामीण इसका समुचित प्रयोग कर सकें।

3. *बिजली :* कुछ वर्षों पूर्व गांव में बिजली के बिल अदायगी एवं शिकायत के लिए एक केन्द्र बनाया गया था, जो जर्जर अवस्था में पहुंच गया है और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। गलियों में उचित बिजली की आपूर्ति नहीं है और बिजली आपूर्ति गांव की हिरनी नहर, पशु चिकित्सालय से महादेव मंदिर तक अति आवश्यक है। गांव में बिजली आपूर्ति घेवरा सावदा और निजामपुर होती हुयी की जा रही है जिसमें बार-बार अवरोध उत्पन्न होता है। बिना अवरोध के बिजली आपूर्ति कंझावला लाडपुर से होती हुयी मेन कुतुबगढ़ रोड के साथ जा सकती है।

4. *पानी आपूर्ति :* गांव से एक पक्की बनी हुयी नहर जाती है जिसकी हालत बहुत ही दयनीय है। प्रशासन के सब प्रयासों के बावजूद यह साफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि हरियाणा से पानी आपूर्ति बंद कर दिया गया है इसलिए हरियाणा से पानी आपूर्ति पुनः लेने की तत्काल आवश्यकता है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति नियमित रूप से नहीं की जा रही है। गांव में पाइपों द्वारा पानी आपूर्ति की जाती है, किन्तु नए लाल डोरा क्षेत्र में लगभग 4 गलियों में पाइप लाइन डलवाना अनिवार्य हैं।

5. *सीवर :* गांव में सीवर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे गांव की नालियों में या तो पानी रुक जाता है या ओवरफ्लो हो जाता है। गांव में चारों ओर कई सड़कें बनी है, जिसे तत्काल सुधार की आवश्यकता है और 1976-1977 से कटेसर गांव की भूमि के साथ सटा गांव जौन्ती की फिरनी ग्रामीणों द्वारा प्रयोग में नहीं आ रही है, क्योंकि इसके साथ लगती कटेसर गांव की कृषि भूमि है और वे लोग इस फिरनी पर अतिक्रमण करते रहते हैं और कुछ कर भी रखा है, इसलिए इस फिरनी के साथ एक सुरक्षा दीवार दिल्ली-कुतुबगढ़ की मुख्य सड़क बनाना आवश्यक है, जिससे अतिक्रमण को रोका जा सके।

6. *सड़कें :* गांव में कई सड़कें बनी हैं जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

7. *शिक्षा :* एक नगर निगम प्राइमरी विद्यालय तथा दूसरा सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय हैं। दोनों विद्यालयों की दशा भी अच्छी नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है और हर विषय के अध्यापकों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य है।

8. *पशु चिकित्सालय :* गांव में पशु चिकित्सालय है, जिसमें पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। इस पशु चिकित्सालय में एक नियमित और समर्पित डॉक्टर की नियुक्ति होना अत्यावश्यक है।

9. *यातायात :* गांव में डीटीसी बसों का आना-जाना बहुत कम है और गांव की शिकायत है कि पुरानी डी.टी.सी. की बसें आमतौर पर गांव से आती-जाती हैं। गांव के बस शेल्टर लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाए गए थे और ये सभी जर्जर हालात में हैं। गांव की बढ़ती आबादी को देखते हुए इसके पुनर्निर्माण की तत्काल आवश्यकता है।

10. *तकनीकी केन्द्र :* गांव में काफी बेरोजगार नौजवान हैं इसलिए एक तकनीकी विकास केन्द्र की आवश्यकता है जहां उन्हें रोजगार संबंधी तकनीकी शिक्षा दी जा सके। गांव के समुदाय का सुझाव है कि इसको फिलहाल बंद पड़े नगर निगम स्कूल (लड़के) की इमारत में खोल दिया जाए। गांव के प्रसिद्ध कलाकार एवं शिल्पकार द्वारा अगली पीढ़ी के लिए शिल्पकला को पुनर्जीवित करने के कार्य को तकनीकी केन्द्र के माध्यम से किया जा सकता है।

11. *पर्यटन :* यह ऐतिहासिक गांव है जो दिल्ली व हरियाणा की सीमा के साथ लगा हुआ है। यह मुगल बादशाह शाहजहां के काल में स्थापित हुआ। पुरातात्विक विशेषताओं से ओत-प्रोत आम-खास, शाही किला, बादशाही कुआं, जिससे भूमिगत पानी की सुरंग गांव में सात एकड़ भूमि पर बने तालाब तक जाती है, गांव में विद्यमान है। तालाब पूरी दिल्ली में सबसे बड़ा है। जौन्ती गांव के इस तालाब के किनारे अति प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परिधि में हरियाणा से लगते हुए गांव को पर्यटन स्थल बनाने के लिए गांव वालों में पूर्ण क्षमता है।

12. *गांव का आधुनिकीकरण :* गांव में नई तकनीक द्वारा गांव को आधुनिक गांव बनाया जा सकता है। पूरे गांव को कम्प्यूटरीकृत और जैविक कृषि को प्रोत्साहन एवं यहां के बुनियादी ढांचे का पुर्निर्माण एवं विकास करके गांव को आधुनिक बनाया जा सकता है जो गांव को एक अलग पहचान प्रदान कर सकता है।

13. *अन्य :* गांव में पांच चौपाल, पंचायत घर एवं एक सामुदायिक केन्द्र है, जिसकी पुनर्निर्माण एंव सुधार की आवश्यकता है। गांव में आंगनबाड़ी की सुविधा भी है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है।

आदर्श गांव योजना के अतंर्गत सरकार द्वारा जो अन्य कदम उठाने की आवश्यकता है, उसमें कम्प्यूटर शिक्षा सहित एक लाइब्रेरी, लड़कियों के लिए सिलाई-कढ़ाई केन्द्र, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा स्रोत केन्द्र और गांव के विकास के लिए सौर ऊर्जा व्यवस्था की अत्यंत आवश्यकता है। समुदाय के सभी सदस्य, स्त्री-पुरुष सुसंगठित हैं और उनमें मिल-जुलकर कार्य करने की तथा जिला प्रशासन की सहायता करने की पूर्ण क्षमता है। गांव के प्रोत्साहित करने वाले श्री जगपाल जौन्ती, सदस्य भारतीय जनता पार्टी, के नेतृत्व में गांव में कई सोसाइटी एवं रिहायसी संस्थाएं हैं, जिससे गांव को काफी लाभ हो रहा है। यदि उपरोक्त सभी समस्याएं एक सीमित समय-काल में सुधर जाती है तो जौन्ती गांव एक आदर्श आधुनिक गांव में परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि महात्मा गांधी का सोपान था।

डॉ. उदित राज द्वारा ताईवान यात्रा

ताईवान एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 60 लाख के आस-पास है। यह देश 40-50 वर्ष की ही आयु का है और इसकी तरक्की देख और सुनकर के हैरान हो जाने वाली बात है। कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से चांग काई सेक जब यहां भागकर के पनाह लिया तो ताईवान का अधिकतर हिस्सा जंगली और पहाड़ी था। हमारा समाज 5-6 हजार वर्ष पुराना है लेकिन ताईवान से बहुत पीछे है और उसका मुख्य कारण है भेदभाव पर आधारित समाज। हम लगभग आधी आबादी महिलाओं को बिठाकर खिलाते रहे क्यूंकि वे उत्पादन में हाथ नहीं बंटा पाती और यह परंपरा के खिलाफ मान्यता है। इस तरह से लगभग आधी आबादी का श्रम, सहयोग, सोच का उपयोग समाज के उत्थान में हम लगा ही नहीं पाये। ताईवान, जापान और थाईलैंड जैसे देशों में जब हम रहते हैं तो देखते हैं कि कामकाज में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं संलग्न है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर के दुनिया के अन्य देशों में महिलाओं का सहयोग अर्थव्यवस्था में लगभग होता है।

ताईवान बारह चीजों में दुनिया में प्रथम स्थान पर है और 22 में दूसरे स्थान पर है। हम अगर अपने देश को देखते हैं तो शायद ही दो-चार मामलों में भारत आगे होगा। लिंग भेद और अलग-अलग रहने से तो देश के विकास पर कुप्रभाव पड़ा ही, यहां की जाति व्यवस्था ने और ज्यादा देश को पीछे धकेलने का कार्य किया।

डॉ. उदित राज, डॉ. एच. के. दुआ, डॉ. संजय जायसवाल ताईवान के सांसदों के साथ

इस छोटे से देश में 250 किलोमीटर की रफ्तार की ट्रेन चला दी है जबकि अभी हम इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। डॉ. उदित राज पांच दिनों (12-16 अक्टूबर, 2014) के लिए ताईवान यात्रा पर गए और वहां के समाज को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और सोचा कि क्यों नहीं भारत ऐसा देश बन सकता है।

डॉ. उदित राज की धर्मपत्नी सीमा राज के जन्मदिन (02 नंवबर, 2014) की झलकियां

जन्मदिन के मौके पर उपस्थित डॉ. उदित राज एवं उनकी पत्नी श्रीमती सीमा राज

इस अवसर पर मौजूद अपार जनता

डॉ. उदित राज के साथ केक काटती हुयी श्रीमती सीमा राज

सीमा राज को केक खिलाते हुए डॉ. उदित राज

डॉ. उदित राज शुभचिंतकों को संबोधित करते हुए।
साथ में हैं पत्नी श्रीमती सीमा राज, सुपुत्र अभिराज, सुपुत्री सावेरी एवं अन्य।

जन्मदिन के अवसर पर डॉ. उदित राज, श्रीमती सीमा राज, परमेंद्र एवं अन्य सभी झूमते हुए

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि अपनी ओर से भी छपवाकर वितरित करें व तैयारी जोर - शोर से करें

अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय

परिसंघ के आवाहन पर अधिकार एवं सम्मान रैली

डॉ० उदित राज (सांसद, लोक सभा)
राष्ट्रीय चेयरमैन

08 दिसंबर, 2014 (सोमवार) को प्रात: 10 बजे लाखों की संख्या में रामलीला मैदान, नई दिल्ली पर एकत्रित हों

18/10/2014

प्रिय साथियों,

अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ अक्टूबर, 1997 में आरक्षण विरोधी आदेशों की वापसी के लिए अस्तित्व में आया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 30/01/1997, 02/07/1997, 22/07/1997, 13/08/1997 तथा 29/08/1997 के आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए गए थे। हमारे आंदोलन के दबाव में आकर संसद ने संविधान में 81वां, 82वां एवं 85वां संशोधन किया जिसके कारण आरक्षण बच सका।

निजीकरण एवं भूमंडलीकरण के कारण जिस तरह का विकास इस देश में हो रहा है उससे समाज दो वर्ग में बंटता जा रहा है एक है मालिक और दूसरा श्रमिक। जिनका उत्पादन शक्तियों पर कब्जा नहीं है, वे इस दौर में मजदूर के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है कि दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों के हाथ में उत्पादन शक्तियों पर कोई मालिकाना हक नहीं है। गत् कई वर्षों से अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करता आ रहा है लेकिन यूपीए की सरकार ने समितियां तो तीन-तीन बनायी लेकिन देश की पूंजीपति संगठनों ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी के नाम पर मामले को रफा-दफा करके इस अधिकार से वंचित रखा है। इस अधिकार का न मिलने का दूसरा कारण यह रहा कि अनुसूचित जाति और जन जाति के हजारों संगठन और नेता गलतफहमी में या इरादतन समाज के संसाधनों का दुरूपयोग करते रहे हैं और कहते हैं कि लड़ाई समाज की है लेकिन वास्तव में वह अपने संगठन को बचाने के लिए शक्ति का उपयोग करते रहे हैं। संगठन बचेगा तभी उनकी नेतागिरी जिंदा रहेगी। दलित समाज के भोले-भाले लोग इसे मिशन समझ लिये लेकिन परिसंघ ने कभी संगठन बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि वह आंदोलन के रूप में ढ़ल गया था और पूरी ताकत से अधिकार के लिए संघर्ष किया लेकिन समाज का सहयोग नहीं मिल सका इसलिए अभी तक ये उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। परिसंघ गैर राजनीतिक संगठन है और इसके मंच पर साल में एक बार दिल्ली में इकट्ठा होने की ही अपील होती रही है। परिसंघ के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वे तो पूर्णकालिक रूप से लगे रहते ही हैं। समाज से अपील है कि राजनीतिक एवं अपने सामाजिक संगठनों से ऊपर उठकर अधिकार प्राप्ति के लिए वर्ष में एक दिन का समय दे दें तो भी हम लड़ाई जीत जाएंगे। क्या एक दिन का समय और एक दिन का वेतन मांगना बहुत ज्यादा है ? लोग केवल एक दिन लाखों की संख्या में दिल्ली में आकर खड़े हो जाएं तो भी राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बन जाएगा तो हमारी मांगे जैसे : आरक्षण कानून बनवाना, पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक संसद में पास कराना, अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989, को मजबूत करने के लिए संसद में लंबित बिल, स्पेशल कंपोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान को आबादी के अनुपात में बजट आवंटन को कानूनी मान्यता, एक राज्य में बना जाति प्रमाण पत्र दूसरे राज्य में मान्य होना, सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, समयबद्ध पदोन्नति, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति, समान शिक्षा एवं सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों की मान्यता जैसे अधिकारों को पूरा कराना बिल्कुल संभव हो जाएगा।

यक्ष प्रश्न यह है कि परिसंघ के ही बैनर के नीचे लोग क्यों जमा हों ? जवाब है कि 1997 से लेकर अब तक किसी संगठन ने एक अधिकार भी समाज को नहीं दिलाया है। जिस दिन परिसंघ नकारा हो जाए, समर्थन मत देना। संवैधानिक संशोधन तो करवाया ही उसके बाद जितने भी अधिकार जोड़े गए चाहे निजी क्षेत्र में आरक्षण को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना और जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए 2001 में एक विशाल दीक्षा, 2006 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण में पैरवी करना, अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम को कमजोर करने का यूपी सरकार के प्रयास को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बचाना, पिछड़ों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू कराने की लड़ाई लड़ना, लोकपाल में आरक्षण, आदि। क्या कोई और संगठन इतने अधिकार दिलवा पाया ?

डॉ. उदित राज दलितों-आदिवासियों की आवाज उठाने संसद में भाजपा की ओर से गए हैं और इसके लिए भाजपा का धन्यवाद। हमें इस बात का गर्व है कि डॉ. उदित राज के आवाहन पर भागीदारी के लिए लोक सभा के चुनाव में दलितों ने भाजपा को सर्वाधिक वोट दिया। सरकार आते ही सकारात्मक कार्य शुरू हुआ। जो अधिकार जन प्रतिनिधि के द्वारा दिए जाते थे, न्यायपालिका उसे छीनने का कोशिश करती थी लेकिन सरकार ने 121वीं संवैधानिक संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायायिक नियुक्ति आयोग जिसमें 6 सदस्य होंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या किसी भी जनतांत्रिक देश में जज की भूमिका जज बनाने में नहीं होती लेकिन भारत में ही ऐसा क्यूं ? यह कार्य दस साल में यूपीए सरकार नहीं कर सकी और मोदी जी के सरकार आते ही अच्छे दिन लाने लगी। इसके अतिरिक्त पार्टी ने उदित राज को संसद में सवाल उठाने का मौका दिया जो अभी तक नहीं उठा। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अनुदान बजट पर संसद में कभी चर्चा नहीं हुयी थी और इस पर बहस डॉ. उदित राज से शुरू हुयी और उन्होंने कहा कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जितना पैसा अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए वह कभी नहीं मिला। पिछली सरकारों ने ऐसी विरासत छोड़ी कि यह आवंटन कभी 8 प्रतिशत से ज्यादा रहा ही नहीं। 2014-15 के प्लान बजट के तहत कुल 5,75,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस बार भी दलितों के लिए 8.79 प्रतिशत का ही प्रावधान है। यदि अनुसूचित जाति की आबादी 15 प्रतिशत व जन जाति की 7.5 प्रतिशत भी मान ली जाए तो अनुसूचित जाति के लिए 86,250 करोड़ रूपए होना चाहिए था जबकि बजट में 50,548 करोड़ रूपए का ही प्रावधान है। इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति के लिए 43,125 करोड़ रूपए का प्रावधान होना चाहिए था जबकि 32, 387 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। अगर हम लाखों की संख्या में इकट्ठा हों तो डॉ. उदित राज को और ताकत मिलेंगी और हमारी मांगें पूरी होगी।

फूले-शाहू या सामाजिक न्याय की विचारधारा मानने वाले से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता और यह परिसंघ का अटूट विश्वास है। जब भारत की शासन सत्ता में दलित, आदिवासी एवं पिछड़े नहीं थे तो देश बाहर वालों का गुलाम था और आजादी के बाद सबकी भागीदारी हुयी है चाहे कम हो या ज्यादा, तो क्या किसी की हिम्मत है कि सोच भी सके कि वह भारत को गुलाम बना लेगा ? हम तो किसी भी दृष्टि से जातिवादी नहीं है लेकिन जो वंचित हैं उनके लिए अधिकार मांग करके एक खुशहाल एवं समतामूलक समाज, एकात्म समाज, एक मजबूत राष्ट्र बनाने के अलावा और हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है ?

भले ही जो लोग डॉ. उदित राज या परिसंघ को न भी मानते हों तो भी समाज के हित के लिए इस अधिकार एवं सम्मान प्राप्ति महा अभियान में 8 दिसंबर, 2014 को रामलीला मैदान, अजमेरी गेट, नई दिल्ली में लाखों की संख्या में प्रातः 10 बजे शामिल हों।

बी. एल. बैरवा, अध्यक्ष, एससी/एसटी रेलवे एम्प. एसो. — **निवेदक** — **अशोक कुमार, महासचिव, एससी/एसटी रेलवे एम्प. एसो.**

भवननाथ पासवान, जगजीवन प्रसाद, डॉ0 अनिल कुमार, एस. पी. सिंह, धर्म सिंह, बलवंत सिंह चार्वाक (उ0प्र0), इंदिरा आठवले, सिद्धार्थ भोजने, प्रकाश पाटिल (महाराष्ट्र), एस. पी. जरावता, महासिंह भूरानिया, मनीराम सरोहा (हरियाणा), तरसेम सिंह, हंसराज हंस, दर्शन सिंह चंदेढ़ (पंजाब), विनोद कुमार (मो.- 9871237186), नेतराम ठगेला, कंवर सिंह, डॉ. नाहर सिंह, एन. डी. राम, रविंद्र सिंह, ब्रह्म प्रकाश, डॉ. धनंजय, डॉ. अंजू काजल, ए. के. लाल (दिल्ली), मूला राम, इन्द्राज सिंह, विश्राम मीना (राजस्थान), हीरा लाल, एच.सी. आर्या, रोहित कुमार, जयपाल सिंह (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहरा (उड़ीसा), परम हंस प्रसाद, बी. भारती, आर. बी. सिंह, पी. के. राय (म.प्र.), रामू भाई वघेला, आर. एस. मौर्या, एन. जे. परमार (गुजरात), एस. करुपैय्या, एम. पी. कुमार, जी. श्रीनिवासन (तमिलनाडु), के. रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), महेश्वर राज, जी. शंकर, आई मैसया, एस. रामकृष्णा, जे. बी. राजू, वाई. एम. विजय कुमार, बी. नरसिंह राव, पी. वी. रमणा (आन्ध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, दिनेश कुमार, दामोदर बौद्ध (झारखण्ड), आर. के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेंद्र (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, जी. वेंकटस्वामी, पुरूषोत्तम दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.)

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
पत्राचार : टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1, फोन : 23354841-42, टेलीफैक्स : 23354843 Email : dr.uditraj@gmail.com

जय भीम ! जय भारत !!

अनुसूचित जाति / जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय

परिसंघ

के आवाहन पर

अधिकार एवं सम्मान

डॉ० उदित राज (सांसद, लोक सभा)
राष्ट्रीय चेयरमैन

महारैली

08 दिसंबर, 2014 (सोमवार) को प्रात: 10 बजे रामलीला मैदान, नई दिल्ली पर

मुख्य मांगें

1. पदोन्नति में आरक्षण के लिए 117वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पास करवाना 2. निजी क्षेत्र एवं न्यायपालिका में आरक्षण 3. सफाई काम में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना 4. खाली पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान 5. समान शिक्षा 6. भूमिहीनों को भूमि 7. आरक्षण कानून बनाओ 8. अनुसूचित जाति योजना एवं जन जाति उप योजना कानून बनाओ 9. एक राज्य का जाति प्रमाण-पत्र सभी राज्यों में मान्य हो 10. महंगाई की दर से छात्रवृति में बढ़ोतरी

बी. एल. बैरवा, अध्यक्ष, एससी/एसटी रेलवे एम्प. एसो.

निवेदक :

अशोक कुमार, महासचिव, एससी/एसटी रेलवे एम्प. एसो.

भवननाथ पासवान, जगजीवन प्रसाद, डॉ0 अनिल कुमार, एस. पी. सिंह, धर्म सिंह, बलवंत सिंह चार्वाक (उ0प्र0), इंदिरा आठवले, सिद्धार्थ भोजने, प्रकाश पाटिल (महाराष्ट्र), एस. पी. जरावता, महासिंह भूरानिया, मनीराम सरोहा (हरियाणा), तरसेम सिंह, हंसराज हंस, दर्शन सिंह चंदेढ़ (पंजाब), विनोद कुमार (मो.- 9871237186), नेतराम ठ्गेला, कंवर सिंह, डॉ. नाहर सिंह, एन. डी. राम, रविंद्र सिंह, ब्रह्म प्रकाश, डॉ. धनंजय, डॉ. अंजू काजल, ए. के. लाल (दिल्ली), मूला राम, इन्द्राज सिंह, विश्राम मीना (राजस्थान), हीरा लाल, एच.सी. आर्या, रोहित कुमार, जयपाल सिंह (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहरा (उड़ीसा), परम हंस प्रसाद, बी. भारती, आर. बी. सिंह, पी. के. राय (म.प्र.), रामू भाई वघेला, आर. एस. मौर्या, एन. जे. परमार (गुजरात), एस. करुपैय्या, एम. पी. कुमार, जी. श्रीनिनवासन (तमिलनाडु), के. रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), महेश्वर राज, जी. शंकर, आई मैसया, एस. रामकृष्णा, जे. बी. राजू, वाई. एम. विजय कुमार, बी. नरसिंह राव, पी. वी. रमणा (आन्ध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, दिनेश कुमार, दामोदर बौद्ध (झारखण्ड), आर. के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेंद्र (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, जी. वेंकटस्वामी, पुरुषोत्तम दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.)

पत्राचार : टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1, फोन : 23354841-42, टेलीफैक्स : 23354843

Email : dr.uditraj@gmail.com www.uditraj.com

डॉ. अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि राष्ट्रीय समिति की बैठक संपन्न

14 अप्रैल, 2015 को निधनस्थली पर स्मारक का भूमि पूजन संभव- सुदर्शन भगत, केंद्रीय राज्यमंत्री

टी. एम. कुमार

नई दिल्ली, 05 नवंबर। दिल्ली के वायएमसीए सभागार में आयोजित डॉ. अंबेडकर निधनस्थली-परिनिर्वाण भूमि सम्मान समिति की राष्ट्रीय बैठक में देशभर के 23 राज्यों के प्रमुख अंबेडकरवादी कार्यकर्ता शामिल हुए। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इंद्रेश गजभिये ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि इस बैठक में चर्चा के उपरांत डॉ. अंबेडकर की निधनस्थली के सम्मान से जुड़ी तीन मांगों का मांग पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री सुदर्शन भगत को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि तीन सूत्री मांगों के समर्थन में आगामी 6 दिसंबर, 2014 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान सभा एवं रैली आयोजित होगी। तीन प्रमुख मांगें है :-1. निधनस्थली पर सांची स्तूप जैसा भव्य स्मारक बनाने, 2. निधनस्थली के निकट के बंगलों का अधिग्रहण कर बड़ा भूमि परिसर उपलब्ध कराने, 3. गांधी समाधी राजघाट जैसा संसद से कानून बनाकर सम्मान का दर्जा देना।

इस राष्ट्रीय बैठक में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री सुदर्शन भगत मुख्य अतिथि थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया, डॉ. संजय पासवान ने प्रमुख अतिथि के रूप में संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सुदर्शन भगत ने बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर की निधनस्थली पर बनने वाले राष्ट्रीय स्मारक का भूमि पूजन आगामी 14 अप्रैल, 2014 को किए जाने की संभावना है। मंत्रालय के द्वारा यह फाइल उनके पास पहुंच चुकी है। बैठक में आभार प्रदर्शन श्री टी. एम. कुमार, राष्ट्रीय संयोजक ने किया। बैठक को श्री सुनील राम टेके, श्री कैलाश सांकला, श्री भवनाथ पासवाना, श्री शांत प्रकाश जाटव, श्रीमती माया ताई चवरे, श्री किरणजीत गेरी एवं श्री परमजीत केंथ आदि प्रमुख पदाधिकारियों ने संबोधित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम का मांग पत्र केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री सुदर्शन भगत को डॉ. परिनिर्वाण भूमि को राष्ट्रीय बैठक में प्रस्तुत किया गया

गुजरात परिसंघ इकाई का सम्मेलन संपन्न

योगराज वाघेला

अहमदाबाद। गत् 31 अक्टूबर, 2014 को अहमदाबाद के मंगणदास टाउन हाल में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के गुजरात इकाई का सम्मेलन संपन्न हुआ। परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद डॉ. उदित राज का सम्मान कार्यक्रम श्री एन. जे. जी. और मौर्या के मार्गदर्शन में श्री रामूजी वाघेला और महासचिव श्री योगराज वाघेला के नेतृत्व में किया गया। परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिल्ली से सांसद डॉ. उदित राज व दिल्ली प्रदेश, भाजपा की महिला मोर्चा की महासचिव श्रीमती प्रीति अग्रवाल का श्री रामूजी और योगराज के द्वारा डॉ. अंबेडकर साहब की मूर्ति और चरखा देकर स्वागत किया गया।

डॉ. उदित राज ने अपने संबोधन में दलित-आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि यदि आप एक होकर के नहीं रहोगे तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मै छड़ी घुमाऊं और आपके अधिकार बच जाये। समाज को एक करना है और समाज की मदद करना है तो आप सबको कंधे से कंधा मिलकार मेरा साथ और सहयोग करना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप पूरे देश में चेतना लाने के लिए साथ देंगे तो मैं जरूर आप के अधिकारों की सुरक्षा कर पाऊंगा।

श्री रामूजी और श्री योगराज ने परिसंघ के उद्देश्य के बारे में बताया कि परिसंघ ने ही दलित-आदिवासियों के अधिकारों को बचाने के लिए सही दिशा में शुरुआत किया था।

इस अवसर पर श्रीमती प्रीति अग्रवाल खास महेमान के रूप में उपस्थित थी। मंच पर पूर्व सांसद वर्माजी, पूर्व मंत्री गुजरात श्री गीरीश परमार, पूर्व विधायक सुनील ओजा और वाल्मिकी निगम के चेयरमैन श्रीमती दर्शनाबेन वाघमेला खास रूप में उपस्थित थे। साथ ही दलित-आदिवासी एवं अल्पसंख्यक समाज के लोग जिसमें बीएएसएनएल, ओएनजीसी रेलवे, कास्टम, एक्साईज, आयकर विभाग के अधिकारी-पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित थे।

Rest of page no. 8 ...

Giant Odisha Convention calls for unity

Convention as Chief Guest and Guest of Honour.

The speakers unanimously called for a united struggle to demand reservation in private sector and judiciary and promotion of SC/ST employees of Odisha as per 85th Constitutional Amendment and 38% reservation for SC/ST students in all educational institutions.

Shri Dharmendra Pradhan lauded the Jana Dhana Programme and Swachh Bharat Abhiyan of the Hon'ble Prime Minister of India. Shri Jual Oram assured the audience to devote his full time to redress grievances of SC/STs of Odisha. Dr. Udit Raj informed how All India Confederation had to struggle to achieve marvelous success in the enactment of 81st, 82nd & 85th Amendment Act for reservation of SCs & STs in employment and promotion which led to the withdrawal of anti-SC/ST orders issued by the Government of India. He urged the participants to show up in large numbers in the Maha Rally at the historic Ram Lila Ground in New Delhi at 10am on 8th December 2014 to achieve our right to reservation in private sector and judiciary and to end contract system in Safai work and to immediately fill the vacant posts meant for SC/ST candidates, amongst other demands. A large number of students from Utkal University and affiliated colleges took a pledge to work united for the rights of SC/STs. The Convention ended with a happy note and vote of thanks by Shri Suresh Saunta, student leader of Utkal University.

Jai Bheem !

All India Confederation of SC/ST Organisations

Jai Bharat !!

Dr. Udit Raj (M. P., Lok Sabha)
National Chairman

Call

For Dignity & Rights

MAHARALLY

at

Ramlila Maidan, New Delhi
on 08th Dec., 2014 (Monday) at 10 AM

DEMANDS

1. Pass 117th Constitutional Amendment to provide Reservation in Promotion
2. Reservation in Private Sector and Judiciary
3. Ban contract system in Safai Work
4. Fill up backlog posts by special drive
5. Right to Equal Education
6. Land to the Landless
7. Enact Reservation Act
8. Legislation of SCP & TSP
9. Caste certificate of one State should be valid in other States
10. Raise scholarship amount as per price index.

B. L. Bairwa, President, AISCTREA

By

Ashok Kumar, Gen. Secy., AISCTREA

Bhawan Nath Paswan, Jagjivan Prasad, Dr. Anil Kumar, S. P Singh, Dharm Singh, Balwant Singh Charwak (UP), Indira Athawale, Siddharth Bhojne, Prakash Patil (M.S.), S.P. Jaravta, Maha Singh Bhurania, Maniram Saroha (Haryana), Tarsem Singh, Hansraj Hans, Darshan Singh Chanded (Punjab), Vinod Kumar (M.- 9871237186), Netram Thagela, Kanwar Singh, Dr. Nahar Singh, N. D. Ram, Ravinder Singh, Brahm Prakash, Dr. Dhananjay, Dr. Anju Kajal, A. K. Lal (Delhi), Moola Ram, Indraj Singh, Vishram Meena (Rajasthan), Hira Lal, H.C. Arya, Rohit Kumar, Jaipal Singh (U.K.), Aalekh Malik, D. K. Behera (Orissa), Param Hans Prasad, B. Bharti, R. B. Singh, P. K. Roy (M.P.), Ramu Bhai Vaghela, R.S. Maurya, N. J. Parmar (Gujarat), S. Karuppaiah, M. P. Kumar, G. Sriniwasan (T.N.), K. Raman Kutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), Maheshwar Raj, G. Shankar, I Mysaiah, S. Ramkrishna, J. B. Raju, Y. M. Vijay Kumar, B. Narsingh Rao, P. V. Ramna (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Dinesh Kumar, Damodar Baudh (Jharkhand), R. K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Kumar Dhirendra (Bihar), J. Shriniwaslu, G. Venkatswamy, Purushottam Das (Karnataka), Seetaram Bansal (H.P.).

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1, Tel : 23354841-42
Email : dr.uditraj@gmail.com www.uditraj.com

Sample of the Handbill for the forthcomming Rally is being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get it printed and distributed

Confederation Call For A Rally For Dignity & Rights

Dr. Udit Raj M.P., Lok Sabha, National Chairman

On 08th December, 2014 (Monday) at 10 AM, Lakhs of People to Assemble at Ramlila Maidan, New Delhi.

18/10/2014

Dear friends,

All India Confederation of SC/ST Organizations came into being in October 1997 to cancel anti-reservation orders dated 30/01/1997, 02/07/1997, 22/07/1997, 13/08/1997 and 29/08/1997 issued by the Department of Personnel & Training, Government of India. Due to our vibrant struggle, the Government made 81st, 82nd and 85th amendments in the Constitution of India and the reservations were protected.

Privatization and globalization have divided the world in two classes – the rich and the poor. Those who do not own means of production will be reduced to labourers. It is very much evident that the Dalits and Adivasis do not own means of production. For the past many years the All India Confederation has been demanding reservation in private sectors but the UPA Government got away with the excuse of making three committees which yielded nothing except an eye-wash under the pretext of 'corporate social responsibility'. Lack of consciousness and existence of multiple organizations came in the way of unity to muster enough support to build the pressure on the Government. These organizations, deliberately or innocently, have been misusing the resources, time and talent under the notion that they are carrying forward the caravan of Baba Saheb Dr. Ambedkar. In fact, most of them have exhausted their energy in protecting their own organization rather than pressurizing the Government to accede to their demands. Why did they waste their energy to protect their own organization, had their vested interests to save their own leadership as office-bearers not been there? So all their efforts were finished before reaching the target and in such a situation, they sometimes harmed the society more than whatever little they could serve it. The innocent Dalits mistook it as a mission and the Confederation never passed through such phase because it got culminated into a nationwide movement just after its making under the visionary leadership of Dr. Udit Raj. Under these circumstances, our goals are still unachieved. We would like to clarify once again that our Confederation is non-aligned to any political party and we appeal to all concerned to come to Delhi to join us on 8th of December 2014 at 10 a.m. at Ram Lila Maidan, Delhi Gate. All are requested to join their hands with us and we are sure to win. One day's time or one day's salary is not a big demand for such a big cause. If lakhs of people come to Delhi to render their support, it will have a great bearing on the Government and the demands like reservation in promotions, redressal of SC/ST grievances, passing of Bill to strengthen the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989, allocation of budget under Special Component Plan and Tribal Sub Plan as per population ratio, recognition of caste certificate of one State in other State, ban on contract system in Safai work and regularizing them and their time-bound promotion, equal education for all and recognition to SC/ST organizations by Government departments. All these rights would become a reality if we all fight unitedly.

The main question arises as to why we should all unite under the banner of Confederation. The answer is that since 1997 not any other organization has achieved even a single right. If we become like any other organization that do nothing, we will not ask for any support and will end up all activities. We have already fought relentlessly for reservation in private sectors, reservation in promotions in the Supreme Court of India in 2006, successfully defended the dilution of SC/ST Atrocities Act by the UP Government in Allahabad High Court, reservation in higher education for OBCs, reservation in Lok Pal, etc., etc. Did any other organization fight for and achieve so many rights for SC/STs and OBCs?

Dr. Udit Raj has reached to the Parliament to raise the voice of weaker section. We thank you and the BJP for this. It was on the call given by Dr. Udit Raj that SC/STs supported BJP in a big way in Lok Sabha elections. The BJP Government has started good beginning by making 21st Constitutional Amendment to make National Judicial Appointments Commission. What is happening is that the rights which we get from people's representatives are being diluted by judiciary. Now the judges will be selected by the Commission comprising six members and one of them will be from SC/ST/OBC. Now there is a chance to get the fairer deal. In no advanced countries like America, England, Germany, Russia or any democratic nation, the judiciary has role to play in their own appointments. Why this practice in India? The UPA Government could not do this job in ten years but the Modi ji made it possible to bring 'good days'. Besides, the party gave the opportunity to Dr. Udit Raj to raise the issues in the Parliament. There had never been any discussion in the Parliament on the Ministry of Social Justice & Empowerment while passing the demand for grant since Independent. Dr. Udit Raj raised the issue of budget allocation for SCs/STs according to their population. In the budget Rs. 50,548 crore is allocated but it should have been Rs. 86,250 crore. For STs the allocation was Rs. 32,387 crore whereas as per Tribal Sub Plan it should be Rs. 43,125 crore. This exploitative policy was pursued by the former Governments. If we could muster support in lakhs under the leadership of Dr. Udit Raj, we will certainly gain dignity and right which other members of Parliament could not do.

The Confederation believes that we are true nationalist and our efforts automatically culminate in strengthening the unity and integrity of India. Thus, believers in social justice are the purest nationalists. Please do not forget the fact that India spent hundreds of years in slavery and insubordination of the foreigners when there was no participation of different communities and castes in the governance of the country. The SCs/STs and OBCs got an opportunity to participate in the governance of the country after Independence and nobody can now think of colonizing it. We are not casteists from any angle. But we are fighting for the rights of the people who are deprived of their rights for centuries. Our main aim is to build a society which can achieve a strong and happy nation. Even those who do not accept the leadership of Dr. Udit Raj and are the part of the Confederation, they should also participate in large numbers for the cause. The cause is supreme. Please join the Rally in lakhs at Ramlila Maidan, Delhi Gate at 10 a.m. on 8th December, 2014.

B. L. Bairwa, President, AISCTREA **By** **Ashok Kumar, Gen, Secy., AISCTREA**

Bhawan Nath Paswan, Jagjivan Prasad, Dr. Anil Kumar, S.P Singh, Dharm Singh, Balwant Singh Charwak (UP), Indira Athawale, Siddharth Bhojne, Prakash Patil (M.S.), S.P. Jaravta, Maha Singh Bhurania, Maniram Saroha (Haryana), Tarsem Singh, Hansraj Hans, Darshan Singh Chanded (Punjab), Vinod Kumar (M.- 9871237186), Netram Thagela, Kanwar Sen, Dr. Nahar Singh, N. D. Ram, Ravinder Singh, Brahm Prakash, Dr. Dhananjay, Dr. Anju Kajal, A. K. Lal (Delhi), Moola Ram, Indraj Singh, Vishram Meena (Rajasthan), Hira Lal, H.C. Arya, Rohit Kumar, Jaipal Singh (U.K.), Aalekh Malik, D. K. Behera (Orissa), Param Hans Prasad, B. Bharti, R. B. Singh, P. K. Roy (M.P.), Ramu Bhai Vaghela, R.S. Maurya, N. J. Parmar (Gujarat), S. Karuppaiah, M. P. Kumar, G. Srinivasan (T.N.), K. Raman Kutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), Maheshwar Raj, G. Shankar, I Mysaiah, S. Ramkrishna, J. B. Raju, Y. M. Vijay Kumar, B. Narsingh Rao, P. V. Ramna (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Dinesh Kumar, Damodar Baudh (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Kumar Dhirendra (Bihar), J. Shriniwaslu, G. Venkatswamy, Purushottam Das (Karnataka), Seetaram Bansal (H.P.).

All India Confederation of SC/ST Organisations
Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1, Tel : 23354841-42, Telefax: 23354843, Email : dr.uditraj@gmail.com

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 17 ● Issue 24 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 November, 2014

Dr. Udit Raj adopts Jaunti Village under Sansad Adarsh Gram Yojna

Rekha Vohra

NEW DELHI, 11th November, 2014. Dr. Udit Raj, Member of Parliament, North West Delhi Parliamentary Constituency, has selected Village Jaunti, Ward no. 29, under Mundka Assembly Constituency-8, to be developed as an Ideal Village under the Sansad Adarsh Gram Yojana.

An Introduction to Village Jaunti (North West Parliamentary Constituency, Delhi)

Jaunti village falls in the North-West Delhi Parliamentary constituency, Outer District of Delhi. It is situated near Kanjhawala-Qutubgarh Road and major part of the village is surrounded by village Chatesar on northern side, Garhi Rindhala on the southern side, Ladpur village on eastern side & Kanaunda, Khairpur & Mukundpur (Haryana) on western side.

According to the revenue records, the area of the village is 9199 bigha 12 biswa. Out of this, 5800 bigha (approximate) is used for the purpose of agriculture, 383 bigha 3 biswa comes under Gram Sabha and remaining comes under abaadi deh, roads, canal, school, playground, ponds, parks, etc. Thus a large part of the village is used for agricultural activities.

The total population of the village is approximately 6,000. (However, census data have not been checked).

Members of different castes and communities live in communal harmony in the village and the villagers claim they have never had communal discord in the village.

Facilities and Main issues to be developed and redressed are –

1. Hospital : Efforts to build a 50 Beds hospital by the DHS Department have been on since 1977. Gram Sabha Land has been allocated for this purpose but decisions have been delayed for 18 years. An urgent resolution to this issue is required.

Presently there is a dispensary run by DHS but there are not enough medicines or doctors.

2. Sports: There is Physical Training Center at the village covering 8 Bighas. This is to be completed by MCD Narela Zone so that the youth and members of the community can use it.

3. Electricity : An Electricity Bill Collection and Complaint Center was built some years ago but needs to be rebuilt.

Adequate street lights are urgently required to be put in the stretch from Firni Mod Canal, Veterinary Hospital to Mahadev Mandir.

Electricity to the Village currently comes in a very circuitous way via Ghevra, Shabad and Nizampur. There are always breakdown problems due to this. A more efficient and direct supply system would be to reroute this via Kanjhawala, Ladpur and Main Qutubgarh Road.

4. Water Supply: There is a pucca Canal running through the village. This is in a very dirty condition, despite all efforts to get it cleaned by the administration. Water supply from Haryana has been stopped and needs to be resumed.

A booster pump run by Delhi Jal Board does not supply enough water regularly. There is piped water supply in the village, but new pipelines are required to put in four lanes in New Lal Dora Area.

5. Sewerage: There is no facility of proper sewerage in this village which often causes clogging & overflowing of water.

6. Roads: Sufficient number of roads has been laid around the village but need lots of improvement.

Also since 1976-1977 the Firni Tatesar road is not being able to be used by the public because of it being agricultural land of Tatesar. Govt. needs to resolve this issue immediately as this is causing great inconvenience to the villagers. A demarcation defence wall along the Firni upto the main Delhi-Qutubgarh Road needs to be built so that no encroachment takes place.

7. Education: There are two govt. schools, one MCD girls primary school (1st to 5th) and other Govt. Sarvodaya Co-Education Vidyalaya, Jaunti (1st to 12th) are running in the village. Both these schools are poorly run. The quality of education needs to be improved, and teachers required to attend regularly.

8. Veterinary Hospital : There is a Veterinary Hospital where there are not enough medicines available. There should be a regular and dedicated doctor deployed for this hospital.

9. Transport: Buses run by DTC are very sparse and poorly run. The villagers complain that DTC sends their oldest buses to the village. All the Bus shelters in the village were built 30-40 years ago and are in a very dilapidated condition. These need to be repaired and new ones built to accommodate the growing needs of the population.

10. Skill Development Center : There are several unemployed youth in the village. A skill development center is urgently needed where they are taught skills to make them employable. The community propose that this can be opened in the land that is currently occupied by MCD School that was shut down.

The village artisans were once famous for producing artful clay pottery. This can be revived and become an income generation scheme under the skill development center.

11. Tourism Development : Jaunti is a historic village situated along the periphery of Delhi-Haryana Border. It was established during the reign of Emperor Shahjahan. Interesting and unique, historical and archeological features include the Aam Khas Fort that has a Shahi well from which an underground tunnel carried water to a tank spread over seven acres. This is the largest water tank in Delhi. There is an ancient Shiva Temple on the banks of the Tank. Jaunti Village has the potential to be developed as a tourism site on the outskirts of the capital.

12. Modernization of Village : The village can be transformed into a modern village by the introduction of the new-age technologies such as digitizing the entire village, introducing organic farming and upliftment of the facade in a special colour which will give the village a unique identity.

13. Others: There are five Chaupal/ Panchayat Ghars, one community centre in the village. These need to be repaired and upgraded. Aanganwadi facility is also available but needs improvement.

Other initiatives to be undertaken by the government under the Adarsh Gram Yojana include library with computers, embroidery and sewing center for young girls, education resource center for school going children and solar energy for village upliftment.

The community members, including women are well organized and have the capacity to work unitedly to assist the District Administration. The members under the encouraging leadership of Shri Jagpal Jaunti (BJP Member) have formed several Societies and Residential Associations for the benefit and progress of the village. Once these problems are addressed and redressed in a time-bound manner, Jaunti Village will be transformed into an Ideal Model Village as envisaged by Mahatma Gandhi.

Giant Odisha Convention calls for unity

Alekh Mallick

Bhubaneswar, Nov 4, 2014: Under the patronage of All India Confederation of SC/ST Organizations, Odisha State Branch, Bhubaneswar organized a State level Convention on 'The Problems of Adivasis & Dalits of Odisha' on 4th November at Rashtrabhasa Prassar Samiti.

Cutting across party lines, social activists from all walks of life participated in the Convention to express their candid views on the problems faced by SCs & STs in the country and Odisha in particular and discuss ways and means to redress them.

The Convention was inaugurated by Dr. Udit Raj, Hon'ble Member of Parliament from North West Delhi Parliamentary Constituency and National Chairman of All India Confederation of SC/ST Organizations. Shri Jual Oram, Hon'ble Union Minister for Tribal Affairs and Sri Dharmendra Pradhan, Hon'ble Minister of State for Petroleum & Natural Gas also participated in the

Rest on page no. 5 ...

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn